The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 1 | January 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

वैश्विक महामारी के बाद की दुनियाँ में सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य का अध्ययन

डॉ. अरूणा कुमारी

(गृह विज्ञान विभाग), रामवृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18648049

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-01-2026

Published: 10-02-2026

Keywords:

स्वास्थ्य यानि कि सेवा क्षेत्र का अध्ययन, प्रमुख सुझाव व योजनाऐं आर्थिक समीक्षा *2024-25* की अनुशंसाएँ, डिजिटल स्वास्थ्य, चुनौतिया तथा चिन्ताएँ।

ABSTRACT

सेवा क्षेत्र यानी की स्वास्थ्य किसी किसी भी समृद्ध समाज का अभिन्न अंग होता है। भारत ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए देश को हर नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा केन्द्रीय बजट 2025-2026 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिये लगभत्र 01 लाख करोड़ रूपए आंवटित किये गए है। वित्त वर्ष 2026 के बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा वित्त वर्ष 2025 में 1.9% से मामूली रूप से बढ़कर 1.97% हो गया, लेकिन समग्र स्वास्थ्य आवंटन बजट के 2% से कम रहा। संघीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये कई प्रस्ताव किये है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान पर खास जोर दिया गया है। रोगों की रोकथाम से संबंधित सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कोविड-19 ने स्वास्थ्य संबंधी आंकडो की गुणवत्रा और उपलब्धता में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया है।

भारतीय स्वास्थ्य यानी कि सेवा क्षेत्र को सबसे बड़े बाजारों में से एक माना जाता है जिसके 2025 तक 638 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान हो भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट 2025 की घोषणा में इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण विकास अवसर के रूप में पहुंचाना है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को 99,859 करोड रुपये के पर्याप्त आंवरन के साथ, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, स्वास्थ्य सेवा संचालन को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण धनराशि निर्धारित की गई है इसके अतिरिक्त दवा उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पी.एल.आई) योजना के लिए 2,445 करोड़

रुपये आंवटित किए गए है, जो इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और नवाचार भो बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। यह धनराशि न केवल स्वास्थ्य सेवा के बुनियारी ढाँचे और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाएगी बल्कि स्वास्थ्य सेवा समानता को भी बढ़ावा देगी। इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगमन पर बीजा की शुरुआत और पहली बार हाशिए पर रहने वाली महिला उद्यमियों की 2 करोड़ रुपये से 5 लाख तक में टर्म लोन की पेशकस जैसी पहले अवसरों को व्यापक बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आर्थिक समीक्षा 2024-2025 और केन्द्रीच बजट 2025-2026 में देश में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई और घोषणा की गई। कई घोषणाओं में से प्रमुख घोषणा डेकेयर कैंसर सेंटर की स्थापना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सुझाव व घोषणाऐं इस प्रकार है किये गए हैं जैसे:-

- **UPF पर कर लगाना** -:
  - आर्थिक समीक्षा 2024-25 ने मोटापे, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर के साथ संबंधों का हवाला देते हुए, उनकी खपत को रोकने में लिये अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों)UPF) पर 'स्वास्थ्य कर' का प्रस्ताव दिया है।
  - UPF की अधिक खपत भारत के विजन में मधुमेह का केंद्र बनने का मुख्य कारण है, जहाँ 101 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित है।
- **कैंसर देखभाल विस्तारः**
  - सरकार ने वित्त वर्ष 2026 तक प्रत्येक जिले में कैंसर रेखभाल केंद्र और स्थानीय कीमोथेरेपी और उपचार के लिये वित्त वर्ष 2025-26 तम नए डेकेचर कैंसर केन्द्र स्थापित करने की 200 योजना बनाई है।
- **जीवन रक्षक दवाओं में छूट :**
  - बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क)BCD) से छूट दी गई है, जिससे लागत कम हो जाएगी, जबकि फार्मा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रम)PRP) शुल्क मुक्त दवाएं उपलब्ध कराना जारी रखेंगी।
  - BCD एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में आयातित सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है।
  - PAP उन लोगों की सहायता करते हैं जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं हैं, वे दवाइयों की पूरी लागत को कवर करते हैं या दवाओं पर छूट प्रदान करते है।
- **गिग वर्कर्स के लिये एबी पीएम -:जेएवाई-**

- ➢ एवी पीएमजेएवाई का विस्तार लगभ-ग 01 करोड़ गिग वर्कर्स को कवर करने के लिये किया गया है, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिये आईडीश्रम पोर्टल पर पंजीकृत -कार्ड के साथ ई-किया जाए।

- **स्वास्थ्य अवसंरचना और जनशक्ति-:**
  - ➢ स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किये जाने और वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु वार्षिक रूप से 3,00,000 स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने हेतु पॉच कौशल केंद्र स्थापित किये जाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन)PM-ABHIM) के लिये 4,200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- **महिला एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल :**
  - ➢ बाल पोषण और टीकाकरण हेतु वित्त पोषण में वृद्धि के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विस्तार किया जाएगा।

नोट:- अधिक मॉंगनवाडी केंद्रों को डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली से उन्नत किया जाएगा।

- **भैषजिक अनुसंधान -:**
  - ➢ सरकार ने भैषजिक अथवा फार्मास्युटिकल विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन)PLI योजना के लिये (2,445 करोड़ रुपए आवंटित किये।
- **मानसिक स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन -:**
  - ➢ समग्र भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु विधि का आवंटन किया गया।
- **चिकित्सा पर्यटन -:**
  - ➢ सरकार भारत में चिकित्सा पर्यटन बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिकित्सा पर्यटन बाजार का मूल्य 7.56-10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में 'हील इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का UPF व्यय वर्ष 2006 में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें खुदरा बिक्री (वर्ष 2011 से वर्ष 2013 में 13.7% की वृद्धि हुई है। घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 के अनुसार UPF हेतु ग्रामीण क्षेत्री के घरेलू खाद्य बजट में 9.6%. और शहरी क्षेत्रों के घरेलू खाद्य बजट में 10.64% का व्यय किया जाता है। ब्राजील, कनाडा, चिली, फ्रांस, मैस्किको, इजरायल, पेरु, यूनाइटेड किंगडम और उरुग्वे जैसे देश UPF की लेबलिंग और विपणन प्रतिबंधों के लिये न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल (NPM) का उपयोग करते हैं। NPM के

अंतर्गत पोषक तत्वों के आधार पर खाद्य पदार्थों की रेटिंग की जाती है। ताकि स्वास्थ्य विकल्पों और स्वास्थ्य हेतु हानिप्रद विकल्पों की पहचान की जा सके।

UPF की खपत में कमी लाने हल आर्थिक समीक्षा 2024-25 में की गई अनुशंसाएँ

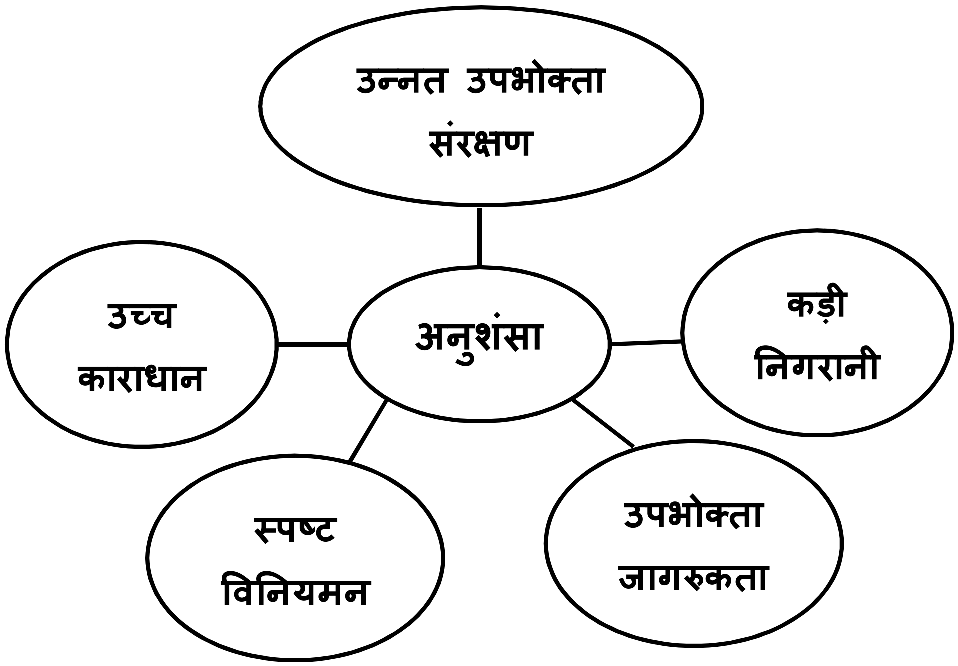

UPF परिभाषाओं और लेबलिंग मानकों सहित सख्त FSSAI विनियमनों की अनुशंसा की गई साथ ही स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और भ्रामक दावों को रोकने के लिये ब्रांडेड उत्पादकों की कड़ी निगरानी किया जाने का सुझाव दिया गया। अतिरंजित विपणन, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों को लक्षित करने वाले विपणन की रोकथाम करने हेतु कानूनों का सुदृीकरण करने की आवश्यकता हो उपयोग को हतोत्साहित करने और लोक स्वास्थ्य पहलों को वित्तपोषित करने के लिये व्यापक मात्रा में विपणन किये गए UPF पर उच्च कर अधिरोपित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये। विशेष रूप से बच्चों के लिये, UPF के स्वास्थ्य जोखिमों, जिनमें मोटापा, मधुमेह और अन्य चयापचय संबंधी रोग शामिल है, के बारे में शैक्षिक अभियान शुरू किये जाने चाहिये।

स्वास्थ्य ढांचा मजबूतीकरण, वैधानिक शिक्षा एवं डिजिटल स्वास्थ्य:- COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा बुनियादरी ढांचे में लंबे समय से चली आ रही कमियों की ओर ध्यानाकर्षण किया था। इसमें अस्पतालों की क्षमता विस्तरों बीमारी सर्विलांस कार्यबल विस्तार में तत्वकाल निवेश की आवश्यकता उजागर हो गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को 37,226,92 करोड रूपए तैयारियों में वृद्धि

करने पर खर्च की जानी है। इसके बावजूद सरकार के महत्वकांक्षी प्रमुख कार्यक्रम NHM में कमीवेश यथा स्थिति बनी हुई है और इसके लिए बजट में कोई उल्लेखनीय प्रावधान नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के बजट में NHM को आंवटित राशि प्रतिशत के रूप में 1 वेजोंबजट दस्ता), 2 (से संकलित 3 और			
वर्ष	NHM बजट करोड़) (.रु	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कुल बजट करोड़) रु(.	अनुपातिक प्रतिशत
2021-22	36,575,50	71,268,77	51.32
2022-23	28,859,73	83,000	34.77
2023-24	29,085,26	86,175	33.75
2024-25	36,000	87,656,90	41.06
2025-26	37,226,37	95,957,87	38.79

स्वास्थ्य विभाग के बजट में PMJAY तथा PMABHIN के लिए किए गए प्रावधान का प्रतिशत 1 वेजइन आंकड़ों को बजट दस्ता),2,3 और से लिया गया है। 4					
वर्ष	PMJAY बजट (.करोड़ रु)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कुल बजट (.करोड़ रु)	अनुपातिक प्रतिशत PMJAY	PMABHIN बजट करोड़) (.रु	अनुपातिक प्रतिशत
2021-22	6400	71,268,77	8.98	Nil	
2022-23	6412	83,000	7.72	4176.84	5.03
2023-24	7200	86,175	8.35	4200	4.87
2024-25	7300	87,656,90	8.32	3200	3.65
2025-26	9406	95,957,87	14.26	4200	4.37

चुनौतियॉ तथा चिंताएँ

अब इस बात पर विचार किया जाना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये आवंटन से ज्यादा-से-ज्यादा अच्छे परिणाम कैसे हासिल किये जाएं? भारत में आने वाले 25 वर्षों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। लिहाजा,

2047 में 100 साल के भारत के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर सोचना अप्रासंगिक नहीं होगा।

पहला स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रभावशाली, समयबद्ध और विज्ञान आधारित संचार अनिवार्य है। दूसरा कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान हमने पाया कि गलत प्रचार स्वास्थ्य सेवा के लिये बड़ी चुनौती है। गलत प्रचार की वजह से कुछ तबकों में टीकों को लेकर हिचकिचाहट और उन्हें लगाने में आना-कानी देखने को मिली। इसके परिणामस्वरूप इन तबकों में टीकाकरण कम रहा। इस घटना से सबक मिलता है कि समयबद्ध, साक्ष्य आधारित और विश्वसनीय संचार, सरकार के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हिस्सा होना चाहिये। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी गलत सूचना के समय पर खंडन के लिये व्यवस्था को स्थापित किया जाना जरूरी है। इससे मौजूदा कार्यक्रमों की आबादी के बीच बेहतर पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी।

कोविड-19 से हमने एक बार फिर जाना कि टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिये ही नहीं, बल्कि किशोरों और वयस्कों के लिए भी है। कोविड-19 के टीकों के अलावा हेप्टाइटिस-बी, मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकल के टीके भी वयस्कों में रोगों को घटाने में सक्षम हैं। ये कुछ विशेष असुरक्षित वयस्क समुदायों के लिये खासतौर से उपयोगी हैं। सरकार ने 2023 में जोखिम वाले वयस्कों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण शुरू किया है। भारत के पास अब किशोरों को सर्वाइकल कैंसर और अन्य रोगों से बचाने के लिये एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) का स्वदेश में विकसित और किफायती टीका है। अब जरूरत यह है। कि इस टीके को किसी सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए सभी वांछित समुदायों में उच्च टीकाकरण हासिल किया जाए।

तीसरा, वैश्विक महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के महत्व को रेखांकित किया है। इससे हमने जाना है कि अच्छी तरह काम करने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं कितनी जरूरी हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जन केंद्रित होनी चाहिये। इनमें रोगों के उपचार के साथ ही उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्द्धन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

चौथा, भारत में व्याप्त फाइलेरिएसिस, कालाजार और सर्प दंश जैसे 11 रोगों को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों की श्रेणी में रखा गया है। नीतियों और कार्यक्रमों में इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन रोगों से निपटने के उद्देश्य से कार्यक्रमों, टीकों और चिकित्सा अनुसंधान के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

पांचवाँ, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की गुणवत्ता और उपलब्धता में भी सुधार महत्वपूर्ण है। कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने हमें स्वास्थ्य संबंधी समयबद्ध, व्यापक और सटीक आंकड़ों के महत्व के बारे में बताया है। इस तरह के आंकड़े स्वास्थ्य से संबंधित फैसले करने तथा गलत धारणाओं और अफवाहों से निपटने में उपयोगी हैं।

छठा, भारत ने 2023 के लिये जी-20 की अध्यक्षता हासिल की है। जी-20 की अध्यक्षता देश के लिये स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को वैश्विक स्तर पर सामने लाने का बेहतरीन अवसर है। भारत को रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौती की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की जरूरत है। महामारियों और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटने के लिये वैश्विक स्तर पर तालमेल की आवश्यकता है। मानवों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में टीकों की उपलब्धता में असमानता देखने को मिली है। जी-20 के देशों को ऐसे सामूहिक कदम उठाने चाहिये जिनसे भविष्य में टीकों की उपलब्धता में इस तरह की असमानता नहीं हो।

सातवाँ, यह समय आयुष्मान भारत कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र जैसी पहलकदमियों का फायदा उठाते हुए सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों की ओर बढ़ने का है। इन पहलकदमियों का उपयोग स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिये किया जाना चाहिये। साथ ही कोविड के बाद के दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने तथा कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिये भी इन पहलकदमियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आठवाँ, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हमें स्वास्थ्य नीति में संघवाद की भूमिका के बारे में भी नये सिरे से सोचना चाहिये। भारत में स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। फिर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक केंद्रीय नीतियां और कार्यक्रम हैं। यह सोचा जाना चाहिये कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में सहकारी संघवाद को किस तरह मजबूत किया जा सकता है। सभी राज्यों को हाल में घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर को लागू करना चाहिये।

नौवाँ, वैश्विक महामारी के बाद के समय में स्वास्थ्य कार्यबल की उपलब्धता और उसके न्यायोचित वितरण को प्राथमिकता देने की जरूरत है। देश में डॉक्टरों की कुल संख्या पर्याप्त हो सकती है। लेकिन 90 प्रतिशत डॉक्टर निजी क्षेत्र में हैं। सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 10 प्रतिशत डॉक्टर होने से स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाने की सरकार की क्षमता प्रभावित होती है। सिर्फ प्रशिक्षित डॉक्टरों की मौजूदगी से ही काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य कार्यबल का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था के बारे में सोचा जाना चाहिये।

दसवाँ, रोग निगरानी प्रणालियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निरंतरता महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के बाद के समय में भारत की रोग निगरानी प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच क्षमता को मजबूत करने के लिये ठोस उपाय किये गये हैं। इनके परिणामस्वरूप राज्यों में अनेक नये विषाणुओं और मंकीपॉक्स के मामलों का जल्दी पता लग सका है। लेकिन रोगों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण, प्रसार और उपयोग की चुनौती बरकरार है जिसमें तेजी से सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये।

ग्यारहवाँ, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और खून की कमी की चुनौती भी बनी हुई है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिये अनेक कार्यक्रम कई दशकों से जारी रहने के बावजूद उनमें कुपोषण और खून की कमी की उच्च दर बरकरार है। इस स्थिति में सुधार

की रफ्तार बेहद धीमी है। रक्ताल्पता की समस्या से निपटने के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने और कुपोषण संबंधी नीतियों की खामियों को दूर करने की ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

बारहवाँ, मानसिक स्वास्थ्य और कोविड के बाद की दीर्घकालिक समस्याओं पर भी तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिये। मानसिक स्वास्थ्य वैश्विक महामारी से पहले भी एक चुनौती था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार देश में हर आठ में से एक व्यक्ति को किसी-न-किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। लेकिन मानसिक-स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों की वजह से इस ओर गौर नहीं किया गया। वैश्विक महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। कोविड के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भ्रांतियों में भी कमी आयी है। इसके परिणामस्वरूप लोग मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के लिये ज्यादा इच्छुक हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से विस्तार के लिये यह उचित समय है। कोविड-19 से प्रभावित 10 में से लगभग एक व्यक्ति में रोग पश्चात् और दीर्घकालिक लक्षणों की संभावना रहती है। सरकार को खास तौर से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के जरिये इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

तेरहवाँ, भारत को विश्व की फार्मेसी माना जाता है। सरकार को इसके अनुरूप टीकों और चिकित्सा विधान पर अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना चाहिये। नये और फिर से उभरते रोगों के संदर्भ में यह खास तौर से महत्वपूर्ण है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित कर रहे अनेक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग उच्च आमदनी वाले राष्ट्रों की अनुसंधान की प्राथमिकता में नहीं आते। लिहाजा. भारत जैसे देशों को इस ओर खास ध्यान देना होगा।

निकर्ष:

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिये कैंसर देखभाल विस्तार और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPF) पर कराधान सहित प्रमुख स्वास्थ्य उपाय प्रस्तुत किये गए हैं। यद्यपि इन पहलों का उद्देश्य पहुँच और सामर्थ्य में सुधार लाना है, फिर भी बुनियादी ढाँचे, कार्यबल और सार्वजनिक विश्वास जैसी चुनौतियाँ अभी भी महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं।

संदर्भ

- इंडियन एक्सप्रेस (6 Feb. 2025)
- Indian Economy (31Jan. 2025)
- Amar Ujala (01 Feb. 2025)

- Express Health care (05 Feb 2026)
- India Budget (2025-2086)
- National Institutes of Health Report
- एन ग्लोवल हेल्थ (2021 जुलाई)
- PIB Report (2025-26)
- Ministry Of Health And Family Welfare Demand 140-46
- स्वास्थ्य विभाग के बजट में PMJAY तथा PMABHIN के बजट में दस्तावेज
- स्वास्थ्य विभाग के बजट में NHM को आवंटित राशि बजट दस्तावेज
- योजन मार्च),2023)